

## : : आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,



सत्यमेव जयते

राजकोट / Rajkot – 360 001

Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in

रजिस्टर्डडाकए.डी. द्वारा :-

DIN-20230564SX0000424663

अपील / फाइलसंख्या/ क

Appeal /File No.

मलआदेशसं /

दिनांक/

GAPPL/COM/STP/1453/2023

845/D/AC/2021-22

23-03-2023

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.): ख

## RAJ-EXCUS-000-APP-132-2023

आदेश का दिनांक / Date of Order:

29.05.2023

जारी करने की तारीख / Date of issue:

31.05.2023

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

- अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सेवाकर /वस्तु एवंसेवाकर , ग राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham:
- अपीलकर्ता %प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-घ

## M/s. Ravikumar Virjibhai Poriya, Ground Floor, Shri Hari 1/4 New Rameshwar Corner, Nr Pipaliya Hall, Gayatri Nagar, Rajkot-360001.

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखि+त जगह की जा सकती है।/ (A)

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/ (i)

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/ (ii)

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग , ज्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए के पाँच 50 लाख रुपए से अधिक हैं तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उसे शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/-रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/ (iii)

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1.000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, बित्त अधिनियम,1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्न S.T.-5में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्राप्त प्राप्त होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग, ज्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/ (B)

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- वित्त अधिनियम,1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सेवाकर, को अपीलीय न्यायिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करने हिगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. (i)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लाग की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

  केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है

  (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम (ii)

(I) प्राचीत के अपनेत्र (प्राचीत के अपनेत्र) (ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम – बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं॰ 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन

्वशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं॰ 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;

(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षण आवेदन कि प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव,
भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई,वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया
जाना चाहिए। (C) A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गईं है और ऐसे आदेश ज़ो आयुक्तु (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जा ड्यूटा कड़ाट इस आधानयम एवं इसका वासन त्रावधाना के तहत नान्य का गई है जार एत जायरा जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account. (v)

(vi)

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नेयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)

यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सिम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in (G)



## <u>:: अपील आदेश ::</u> :: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Ravikumar Virjibhai Poriya, Ground floor Shree Hari, ¼ New Rameshwar Corner, Near Pipaliya Hall Gayatri Nagar, Rajkot Gujarat 360001 (hereinafter referred to as "Appellant") has filed present Appeal against Order-in-Original (OIO) No. 845/D/AC/2021-22 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division-I Rajkot (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- The facts of the case, in brief, are that Income Tax Department 2. provided data/ details of various Income Tax payers, who in their Form 26AS for financial year 2016-17 declared to have earned income by providing services classified under various service sectors. The jurisdictional division office called for the information/ documents. No reply/ response was received from the Appellant and in absence of any detail/information/documents from the appellant, for quantification of taxable value, no option was left but to invoke the provision of Section 72 of the Finance Act, 1994 i.e. "Best Judgement Assessment" to determine the amount to be demanded. The amount demanding the Service Tax was determined on the basis of data/ details provided by the Income Tax department and culminated into Show Cause Notice dated 11.10.2021 invoking extended period of 5 years proposing to demand Service Tax of Rs. 1,63,970/-, including all cesses under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') with interest under Section 75 of the Act, and proposing to impose penalty under Section 77(1)(a), 77(2), 77(1)(c) and Section 78 of the Act.
- 3. The adjudicating authority vide the impugned order confirmed Service Tax demand of Rs. 1,63,970/- under Section 73(1) invoking extended period of 5 years along with interest under Section 75 of the Act. The adjudicating authority-imposed penalties of Rs. 10,000/- under Section 77(1)(a), 77(1)(c) and Section 77(2) of the Act. The penalty of Rs. 1,63,970/- was also imposed upon the Appellant under Section 78 of the Act.
- 4. The Appellant has preferred the present appeal on 30.05.2022 on various grounds mainly as stated below:

The adjudicating authority has wrongly confirmed demand of Service Tax of Rs. 1,63,970/- under Section 73(1) of the Act, erred in valuation of taxable Services, erred in not allowing the benefit of Notification No. 33/2012 dated 20.06.2012, erred in demand of interest u/s 75 of the Act, erred in demanding penalty u/s 77(1)(a), 77(1)(c), 77(2) and 78 of the Act.

Personal hearing in the matter was held on 02.05.2023 which was

B.A

5.

attended Shri Bhaskar Joshi, Advocate, wherein he requested to allow threshold exemption of Rs. 10 Lakh on the gross income. The appellant is willing to discharge tax liability of Rs. 5,588/- on this redetermined amount. He also requested to take a lenient view while imposing penalty.

- 6. Appellant has submitted they are engaged in providing work contract services to construction of commercial or residential construction and was not aware about service tax applicable on work contract service and they did not take Service Tax registration or not filed periodic returns. During F.Y. 2016-17 they earned income of Rs. 10,93,127/- for providing work construction services. Appellant submitted Income Tax returns for F.Y. 2015-16 & 2016-17, Profit & Loss account, 26AS, copy of work contract income ledger, copies of invoices etc. Appellant has submitted that in F.Y. 2015-16 income from work contract service was Rs. 8,57,865/-, i.e. below threshold limit of Rs. 10 Lakhs and therefore benefit of threshold limit is available to them in F.Y. 2016-17 and thus taxable value comes to Rs. 93,127/-. Work contract service is also eligible of 60% abatement, therefore after deducting abatement taxable value comes to Rs. 37,251/- and Service Tax payable on it comes to Rs. 5,588/-.
- 7. I have carefully examined the show cause notice, impugned order, appeal memorandum and written submission and additional submission of the Appellant. Adjudicating authority has calculated the taxable income as Rs. 10,93,127/- this amount consists of contract income being ineligible for exemption. Service Tax quantified on value of Rs. 10,93,127/- comes to Rs. 1,63,970/-. The issue to be decided in the present appeal is whether amount of Rs. 10,93,127/- reflected as taxable value in impugned order are taxable or otherwise.
- 8. Going through the documents for F.Y. 2015-16 viz. 26AS, Income Tax return, profit & loss account, I find that appellant has earned income of Rs. 8,57,865/- from Work Contract service and this value of income is less than threshold limit of Rs. 10 Lakhs. Therefore, benefit of threshold limit as per Notification No. 33/2012-ST dated 20.06.2012, is available to appellant in succussive F.Y. i.e. in 2016-17 (relevant period)-.
- 8.1 From the submitted documents viz. ledger of work contract income and invoices thereof, I observed that appellant has provided work contract service for new work and abatement of 60% is to deducted from the value to arrive at net taxable value, as per Valuation Rules i.e. 40% of the value is to be considered as net taxable value. To arrive at net taxable value and payable service Tax amount, after allowing benefit of threshold limit of Rs. 10 Lakhs and deduction of 60% abatement, calculation is as under:

Asin

Particulars		Amount (Rs.)
Taxable value as per impugned Order		10,93,127/-
Taxable value after allowing threshold lim Lakhs (10,93,127-10,00,000 = 93,127)	nit of Rs. 10	93,127/-
Net taxable value after deducting applicabl of 60% of value (93,127 – 55,876 = 37,25		37,251/-
Applicable Service Tax on net taxable va $37,251 = 5,588$ )	lue (15% of	5,588/-

- 9. Accordingly, as per the worksheet shown above, the service tax liability is determined at Rs.5,588/- on the basis of relevant financial records/documents. I uphold charging of interest under Section 75 of the Finance Act, 1994, on redetermined tax amount of Rs. 5,588/-. I also uphold penalty of Rs. 5,588/- under Section 78 of the Finance Act, 1994. However, I extend option of 25% reduced penalty as per second proviso to the Section 78(1) of the Act, subject to the conditions specified therein such as tax, interest and penalty being paid within 30 days of receipt of this order. Further, in view of the facts and circumstances, I impose reduced penalty of Rs. 2,000/- each under Section 77(1)(a),77(1)(c) & 77(2) instead of maximum prescribed penalty of Rs. 10,000/- under each of these sections imposed by the adjudicating authority.
- 10. In view of above, the impugned order dated 23.03.2023 is modified as above.
- 11. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- 11. The appeal filed by Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

बी. शेस. राणा / B. S. RANA अधीराक् / Superintendent

के. ब. एवं सेया कर अपोल्स, राजकोट CGST Appeals, Rajkot (शिव प्रताप सिंह) (Shiv Pratap Singh) आयुक्त (अपील)

Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To, M/s. Ravikumar Virjibhai Poriya, Ground floor Shree Hari, ¼ New Rameshwar Corner, Near Pipaliya Hall Gayatri Nagar, Rajkot Gujarat 360001. सेवा में,

मे॰ रविकुमार विरजिभाई पोरिया, ग्राउन्ड फ्लोर, 1/4 न्यू रमेश्वर कॉर्नर, पिपड़िया हॉल के पास, गायत्रिनगर, राजकोट, गुजरात - 360001 ।

प्रतिलिपि:-

भुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
) अपर/सयुंक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट-। मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट-। मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
। गार्ड फ़ाइल।